

विचार बिन्दु

आशा अमर है उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। -महात्मा गाँधी

भाजपा की ऐतिहासिक जीत-जनता की अपेक्षाएं

नवंबर 2023 में पांच राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, जिनमें से चार विधानसभाओं के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुए हैं। इनमें से तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को सत्ता से हटाकर कर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। वहाँ 119 सीटों में से 65 सीटों पर विजय प्राप्त कर कांग्रेस ने सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त किया है। शेष तीन राज्यों - राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी ओपिनियम और एक्जिट पोल को गलत सिद्ध करते हुए ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। राजस्थान में भाजपा को 199 में से 115, मध्य प्रदेश में 230 में से 162 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। किसी भी ओपिनियम पोल में (एक अपवाद को छोड़कर), इस प्रकार का अनुमान नहीं लगाया गया था।

स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता गदगद हैं। कुछ दिनों में, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इन राज्यों की सत्ता संभाल लेंगी। इस ऐतिहासिक विजय पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई। हम इस लेख में मुख्य रूप से राजस्थान के मतदाताओं की नई सरकार से अपेक्षाओं पर बात करेंगे। पूर्व में सभी एफ़्टड पोल द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई थी कि राजस्थान में कांग्रेस की टक्कर होगी एवं कोई भी दल, बहुत मुश्किल से अपनी सरकार बना पाएगा। ऐसा भी लगता था कि ऐसा करने के लिए उसे अन्य दलों एवं निर्दलीयों की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसा कि पिछली बार कांग्रेस को करना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ एवं भाजपा अपने स्वयं के बलबूते पर अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य के लिए यह अच्छा संकेत है, क्योंकि निर्दलीयों के भरोसे चलने वाली सरकार में हमेशा अस्थिरता की भावना रहती है। ऐसी सरकार में विधायक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कई बार वे एक प्रकार से सरकार को जगहित के निर्णय लेने में बाधक भी बनते हैं। गलतोलत सरकार के समय में देखा गया था कि सरकार का अस्तित्व और विधायकों के मनमर्जी पर टिक गया था और इसका भरपूर लाभ विधायकों ने उठाया। सत्ताधारी दल के विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी बहुत है, इसकी संभावना तो पहले से व्यक्त की जा रही थी, किंतु कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाई कि अधिकांश विधायकों को उम्मीदवार न बनाए। इसका खासियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में भुगताना पड़ा है।

एक और कारण जो कांग्रेस को हार के लिए संभावित लगता है वह है, हाई कमान का असहाय होना। ऐसा लगता था, जैसे राजस्थान के सन्दर्भ में कांग्रेस का हाई कमान कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जब यहां राजस्थान में विधायक दल की बैठक में नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जाना था तो कांग्रेस के ही कुछ मंत्रियों ने इसकी अग्रदृष्टि को छोड़कर समानांतर बैठक बुलाकर चुनाव हाई कमान को ही चुनौती दे डाली। केंद्रीय नेतृत्व के बारे में अपमानजनक बयान राज्य के मंत्रियों तक न दिए, फिर भी हाई कमान मुक दर्शन को हा भी नहीं। भाजपा में ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

पूरे चुनाव प्रचार अभियान में केवल मुख्यमंत्री ही केंद्र में बने रहे। गत कुछ माह से मीडिया में केवल मुख्यमंत्री का ही चेहरा दिखाई देता था। सामूहिक नेतृत्व की बात को तिलांजलि सी दे दी गई थी। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गलोलत के एक साथ होने की तस्वीर भी छपाई गई, किंतु अंदर कहीं ना कहीं समाज के एक बड़े वर्ग में सचिन पायलट से उनका वाजिब अधिकार छीने जाने को एक कसक उभरे मन में थी। इसका प्रदर्शन उन्होंने चुनाव के समय मन देते समय किया। यह सर्वविदित है कि गलोलत सरकार के प्रारंभिक चार वर्षों में केवल अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने में ही निकल गए। पुरा समय, जैसे-जैसे विधायकों को अपने साथ बनाए रखना और येन केन प्रकारेण सरकार को बनाए रखना ही पहली प्राथमिकता हो गई। यह कल्पना की जा सकती है कि उस राज्य सरकार में शासन और प्रशासन की क्या स्थिति होगी, जहां उसका पूरा समय केवल अपने विधायकों को संभालने में ही निकल जाए। इसी का यह परिणाम था कि राज्य में सुशासन का कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलता था। महिलाओं पर बलात्कार और शोषण के मामलों निरंतर बढ़ते रहने से राज्य की बहुत बदनामी हुई। मंत्री, विधायक और अधिकारी मनमानी करने में लगे थे। जनकल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गईं, उनका लाभ भी प्रभावी रूप से वंचित वर्ग को नहीं मिल सका। फलस्वरूप जितना अधिक प्रचार इन योजनाओं का करोड़ों रुपये के विज्ञापनों के द्वारा किया गया, उतनी ही लोगों की अपेक्षाएं तो बढ़ीं, किंतु उनको अपेक्षा के अनुसार लाभ न मिल पाने के कारण उन्होंने स्वयं को टागा सा महसूस किया।

इस परिणाम से एक और संकेत मिलता है, वह यह कि जनता को केवल मुफ्त की वस्तुएं देकर आप उनसे उनका मत खरीद नहीं सकते। राजस्थान में इस संबंध में कई प्रकार के प्रयास किए गए, विशेष कारण

इस परिणाम से एक और संकेत मिलता है,

वह यह कि जनता को केवल मुफ्त की वस्तुएं देकर आप उनसे उनका मत खरीद नहीं सकते। राजस्थान में इस संबंध में कई प्रकार के प्रयास किए गए, विशेष कारण अंतिम तीन-चार माह में, जैसे महिलाओं को मोबाइल बांटना, सस्ती रसोई गैस देना, मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्रति वर्ष 12000 रुपये देने की घोषणा हो।

सुरक्षा हो। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और लोक सेवा आयोग के चयन एवं अन्य चयन प्रक्रियाओं में बहुत धांधली सामने आई। युवाओं के समक्ष रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है और यदि पद रिक्त होने के बाद भी योग्य व्यक्तियों को समय पर चयन होकर उन्हें नियुक्ति न मिले तो उनके मन में आक्रोश पनपता है जिसका प्रकटीकरण चुनाव में होता है।

एक नया मुख्यमंत्री राजस्थान को शीघ्र मिल जाएगा। वैसे तो राजस्थान में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में शासन बदलने की प्रवृत्ति है। जनता इनके अलावा और कर भी क्या सकती है कि जब भी उसे मौका मिले मत के प्रयोग के माध्यम से सत्ताधारी दल में परिवर्तन लाए। हर बार सरकार बदलने के रिवाज से एक सीख यह शासन संभालने वाली को लेनी चाहिए कि जनता अच्छे शासन, चुस्त प्रशासन, संवेदनशील और ईमानदार प्रशासन की अपेक्षा नहीं सरकार से करती है। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 18-20 वर्षों से एक ही दल की सरकार है और यहां पर इस बार शासन बदलने का अनुमान गलत सिद्ध हुआ। इसका अर्थ यही निकलता है कि वहां पर जनता ने वहां की राज्य सरकार द्वारा किए गए शासन को पसंद किया एवं अल्पकालीन बहुमत के साथ इस सरकार को फिर सत्ता में लेकर आए। जब कांग्रेस को बहुमत 2018 में मिला तो भी वह अधिक समय तक शासन संभाल नहीं पाए और एक डेढ़ वर्ष में ही सत्ता गंवा फिर विपक्ष में आ गए।

भाजपा के शीघ्र नेतृत्व को राजस्थान के लिए सुयोग्य सर्व-स्वीकार्य मुख्यमंत्री का चयन शीघ्र ही करना होगा। वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जनता को संवेदनशील ईमानदार और सुशासन प्रदान कर वंचित लोगों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ सही रूप में पहुंचाने का कार्य कर सके और बेईमान नौकरशाही पर पूर्ण अंकुश लगा सके। उन्हें अधिक समय इस पर नहीं लगाना पड़ेगा कि विधायकों को संभाल कर रखें।

नई सरकार को यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि गत विधानसभा चुनाव - 2018 में इन तीनों राज्यों में बहुमत से कांग्रेस सरकार बनी थी। उसके बावजूद जून, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर दो लोकसभा सीट ही कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। यदि इससे कुछ सीख मिलती है तो यह है कि आगामी चार-पांच महिनो में नई सरकार को सिद्ध करना होगा कि वह पहले की सरकार से कुछ अलग प्रकार की है एवं वह केवल लोक लुभावने वाले ही नहीं करती अपितु लोगों को अच्छा शासन भी देने की योग्यता एवं क्षमता रखती है। ऐसा करते समय सर्व धर्म, जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर जीने की अपराधी तत्व अथवा भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचारी हों उन पर कडा अंकुश लगायें होगा ताकि जनता को सरकार के द्वारा प्रत्याहृत होने से एवं भ्रष्टाचार का दर्श झेलने से राहत मिल सके। यदि इस अवधि में वह अच्छा शासन जनता की अपेक्षा अनुसार देने में सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर संभव है कि इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में सत्ता धारी दल अर्थात् भाजपा को उठाना पड़ सकता है।

इन परिणामों ने एक बार पुनः यह सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक जनता में स्वीकार्यता थावनात है। उन्हें इन तीनों राज्यों की शासन व्यवस्था पर एक निगाह रखनी पड़ेगी, ताकि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार का क्रियाव्यवहन इन राज्यों में हो रहा है, यह सुनिश्चित किया जा सके। जनता ने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ भाजपा को इन तीनों राज्यों का शासन सौंपा है और यह उम्मीद करती है कि वह जनता के सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेगी।

इन परिणामों ने यह भी दिखा दिया कि जनता ने जातिगत जंगणना की बात को महत्व नहीं दिया एवं भाजपा द्वारा जातिगत जंगणना की बात को अस्वीकार करने के बावजूद उसे सत्ता में बिठाया है। यह राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है कि देश की सत्ताधारी पार्टी विभाजनकारी प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सबके लिए कल्याण की बात सोचती है। इस संकेत को 'इंडिया एलाइंस' को भी समझना होगा कि केवल जनता को बरालाकर, जाति-पाति में विभाजित करके अब समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता है।

तेलंगाना के परिणाम ने यह अवश्य बता दिया कि जिस प्रकार का जादू भाजपा का इन तीनों राज्यों में चला उसी प्रकार का दक्षिण के राज्य तेलंगाना में नहीं चला। वहां 10 वर्षों से शासन में भारत राष्ट्र समिति को अपदस्त्व कर कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया है। यदि वहां पर वह अच्छा शासन दे पाती है, तो भाजपा के लिए दक्षिण भारत में प्रवेश करने हेतु और प्रतीक्षा करनी होगी। उत्तर और दक्षिण का यह अन्तर, देश के लिए वष संकेत देता है, इसको समझना कठिन है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश के सर्वमान्य नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो उन्हें केवल उत्तरी भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी अपने जड़ों को मजबूत करना होगा। ऐसा कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, इसका भी विश्लेषण भाजपा के उच्च नेतृत्व को करना पड़ेगा। हाल ही में वह कर्नाटक को खो चुकी है और अब वह तेलंगाना में प्रयास करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। तमिलनाडु और केरल में तो वैसे ही भाजपा की कोई पहचान नहीं बन पाई है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी भाजपा के कंधे पर डाली है। जनता सही अपेक्षा कर रही है कि शीघ्र ही नई सरकार बने और उसे सुशासन उपलब्ध कराए जहां अधिकारी गण अपनी मनमानी न कर पाएं एवं विधायक गण केवल तबादले की ही राजनीति में उलझ कर ना रहे जाए। उसे आवश्यकता है अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था की, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की और सुरक्षित संचालन की। यदि सरकार आने वाले समय में महिलाओं की परिभाषा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और स्वास्थ्य उपलब्ध करा पाई, रोजगार के अवसर उपलब्ध करके चयन प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाई तो, उसे लगना कि उसने भाजपा को सत्ता सौंप कर सही काम किया है। जनता ने तो अपना काम कर दिया, अब सरकार को बारी है कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इस हेतु नई सरकार को अनेकानेक शुभकामनाएं।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. (प्रो.) वीर बहादुर सिंह

मैं कई वर्षों के प्रयास से भी इस पहिली को नहीं सुलझा पाया कि जन प्रतिनिधि इस देश में एक दो बार विधायक/सांसद बनते ही करोड़पति अथवा अरबपति कैसे बन जाते हैं और अकूत संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं? क्या यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता है अथवा कमजोरी अथवा कुछ और? यदि यह कमजोरी है तो इस लुट और डकैती को प्रतिबंधित करने के लिए कारगर उपाय संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक क्यों नहीं किये गए? उत्तर साफ है कि विधायक अथवा सांसद इसमें दखल देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारें? एक तीसरा जरिया सुप्रीम कोर्ट भी है लेकिन वे क्यों सरकार से लड़ेंगे? चुनाव आयोग अब श्री शोषण के बाद निशक्तजन की श्रेणी में आ चुका है।

चुनाव लड़ने को तो मेरे में शक्ति है और ना ही कोई अन्य स्वाध्य है। तो इस खेल की व्यूह रचना समझने की जिज्ञासा असें से पाले हुए है लेकिन कोई अवसर नहीं मिला कि देश के लोकतंत्र

की इस विशेषता को समझ पाया। कुछ वर्षों पूर्व मेरे कुछ परिचित विधायक और सांसद भी थे। परन्तु मैंने कभी उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया इसलिए मैं उनसे काफी स्पष्ट और न की जाने वाली बात भी कह लेता था। उपरोक्त पहिली को सुलझाने के बारे में भी मैंने उनसे पूछा तो वे हंस कर टाल जाते और कहते कि कोई काम हो तो बताओ। ऐसे किसी राजनैतिक नेता से भी सम्बन्ध रखने में मैंने स्वाध की हावी नहीं होने दिया, जिससे मेरा उनसे सम्बन्ध उनके मरते दम तक बना रहा।

आज जब मैं अस्सी वर्ष से अधिक हूँ। मैंने आरम्भ के 22 वर्ष शिक्षा में बिताये और बाद के लगभग 40 वर्ष उच्च शिक्षा व अनुसन्धान में विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं में गुजारे, और अंत में विश्वविद्यालय के उच्च तम शिक्ष कुलपति के पद पर आसीन रहा। कार्य की दृष्टि से पूर्ण संतुष्ट रहा। आर्थिक स्तर भी कमोवेश ठीक ही रहा। लेकिन अब सेवा निवृत्ति के पश्चात् पूर्व काल के विश्लेषण में काफी समय देता हूँ तथा समाज के अन्य वर्गों से समानता के आधार पर पाता हूँ कि मैंने सेवा काल के 40 वर्ष बेकार ही नष्ट किये। क्योंकि मैं दूसरों की भांति एक करोड़ की सम्पत्ति भी नहीं जोड़ सका और अपने दो बेटों और दो बेटियों में किसी को मेडिकल, अभियांत्रिकी अथवा बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ा सका। यह व्यथा मुझे आज तक कचोट रही है। खैर, यह तो एक व्यक्तिगत मामला है क्योंकि मेरे जैसे अनेक लोग इस देश में होंगे जो मेरे जैसा ही अल्पव्यय रहते हैं। एक बार में यह हिसाब लगाने बैठा

कि इस देश में समस्त विधायकों और सांसदों पर सरकार वेतन, भत्ते, पेंशन, टेलीफोन आदि विभिन्न मदों पर वार्षिक कितना धन खर्च करती है? मेरा दिमाग चकरा गया जब सोलह अरब तक आंकड़ा पहुँच गया। उस गणना को मैंने वहीं त्याग दिया। आश्चर्य तो इस बात का है कि इस प्रकार की सूचना अथवा आंकड़े गूगल पर भी नहीं मिलते। इसलिए देश की जनता इस पक्ष पर हमेशा अनभिज्ञ ही रहती है।

इस सन्दर्भ में मुझे एक पौराणिक कथा शंकराचार्य और मंडन मिश्र की पत्नी के बीच हुए ज्ञान सम्बन्धी सम्वाद की याद आ रही है। कथा की सही कड़ियों संजोने में भूल हो सकती है फिर भी उसे यथा भावार्थ रूप में यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बार शंकराचार्य और मंडन मिश्र की पत्नी के बीच धर्म पर सम्वाद शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के बीच मंडन पत्नी ने शंकराचार्य को यौनि सम्बंधित किसी लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक

सम्पदा जा सकता है और वर्णन करने में व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। अतः जन प्रतिनिधिओं की सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने की कला को सीखने-समझने के लिए मेरा एक बार किसी प्रकार जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। चुनाव में लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके लिए धन नहीं है और न ही मेरी जनता के बीच ऐसी कोई प्रसिद्धि जो मैं चुनाव जीत सकूँ। अतः मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे एक बार विधायक अथवा सांसद नामिनेट कर सदन में पहुँचा दें। मेरा इस बाबत कोई प्रलोभन नहीं है। बस यह देखना चाहता हूँ कि सम्पत्ति कैसे बढ़ती है? मैं शायद पूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त कार्य काल में मेरी संपत्ति में जो भी अवाजिब बढ़ोतरी होगी उसे मैं कार्य काल समाप्ति पर सरकार को स्वतः ही लौटा दूँगा और सरकार को संपत्ति वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं दूँगा जब तक कि नतीजे और उनके लिए विवर्ण एकत्रित न कर लें। यद्यपि मैं राजनीत का खिलाडी नहीं हूँ। मेरी संपत्ति में वृद्धि अन्य की अपेक्षा कम ही रहेगी। अतः इस बढ़ोतरी को मैं न्यूनतम मान लूँगा, और अन्य पुराने जनप्रतिनिधिओं के बारे में आंकलन कर निष्कर्ष निकालूँगा।

मेरे विचार से जनता भी यह जानना चाहेगी कि जनप्रतिनिधिओं की सम्पत्ति किस प्रकार बढ़ती है? उस मैकेनिज्म को समझने में मैं सफल हो जाऊँगा। अर्थात् तो मैं यह भी चाहता हूँ कि देश के हर इच्छुक नागरिक को एक बार जनप्रतिनिधि बनाने का प्रावधान भी किया जाय। जिससे वह कम से कम एक